भविष्य में इंडियन एयरलाइंस के नेटवर्क का विस्तार करना संभव नहीं है। मैसर्स जैगसन एयरलाइंस तथा मैसर्स यू॰पी॰ एयर ने इस क्षेत्र को उड़ान प्रचालित करने में अपनी रुचि व्यक्त की थी। राज्य सरकार ने 28 अगस्त, 1998 को निम्नलिखित सूचना दी थी कि:

— लखनऊ, देहरादून और पंतनगर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय पार्किंग, अवतरण और दिक्सूचनात्मक प्रभारों का वहन वे करेंगे,

— राज्य सरकार लखनऊ-पिथौरागढ़-पंतनगर-दिल्ली-देहरादून-सेक्टर पर दो सीटों का उत्तरदायित्व लेगी।

— लखनऊ-पिथौरागढ़-पंतनगर-दिल्ली-देहरादून मार्ग पर प्रचालन करने वाली विमान कंपनियों को विमानन टरबाइन ईंधन पर बिक्रीकर से छूट-प्राप्त होगी। यह राशि राज्य सरकार द्वारा इन विमान कंपनियों को अनुदान के रूप में दी जाएगी।

ये सुविधाएं एक वर्ष तंक बनी रहेगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने औली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में राज्य सरकार द्वारा हवाई पट्टी विकसित करने के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित किया था। इस संदेश में गौचर में हवाई पट्टी का कोई जिक्र नहीं था। केन्द्र सरकार ने किसी भी हवाई पट्टी का विकास पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कोई संदेश नहीं भेजा है।

Augmentation of Central Road Fund

*226. DR D. VENKATESHWAR RAO:
SHRI YERRA NARAYANA SWAMY:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Standing Committee on Transport and Toursim has expressed concern for not augmenting the Central Road Fund as per Parliament Resolution;

(b) if so, the reasons for not implementing the decision so far; and

(c) the measures proposed to enhance the Central Road Fund immediately?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND THE MINISTER OF SURFARE TRANSPORT (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) Yes, Sir.

(b) Due to financial constraints the revised Resolution of Parliament which was passed by both Houses of Parliament on 13.5.88 could not be implemented so far.

(c) The matter is still under consideration of the Government.

Upgradation/construction of airports

*227. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state the details of steps taken/contemplated by Government to upgrade the existing and to set-up new airprots in the country?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): Development/upgradation of airports is a continuous process.

New domestic airport at Tura (Meghalaya) funded by State Government is being constructed by AAI which is likely to be completed by March, 1999.

New domestic airport at Kargil (J&K) is being developed by Airports Authority of India and is likely to be completed by October. 1999.

New airport suitable for Boeing 737 operations has been constructed at Lengpui (Mizoram) Airport by the State Government.

Upgradation of Ahmedabad. Calicut. Hyderabad and Bangalore airports has been taken up. Mysore and Hubli airports have been identified for upgradation. Proposals are also under consideration for developing new airports at Ajmer. Hasan & Gulbarga.

A new airport of international standards has already been developed at Nedumbassery near Cochin by the Government of Kerala and which is likely to become operational by April, 1999.

Further, development of airports of international standards with private paricipation at Mumbai. Bangalore. Hyderabad and Goa are under examination. At Amritsar, the existing airport is proposed to be upgraded to international standards, at an estimated cost of Rs. 120 crores, during the 9th plan period.

At least five cities are being identified for devleopment/construction of world-class international airports with 100% foreign investment. A high-level Task Force under the Chairmanship of Dy. Chairman, Planning Commission is looking into this proposal to identify the locations for the new world-class international airports.

Setting up Cargo hubs at International Airports

*228. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 156 given in the Rajya Sabha on 1st December, 1998, and state:

(a) how Government propose to meet the expendure to be incurred on developing Delhi as a 'Major Cargo Hub';

(b) whether Government intends to extend this scheme of cargo hubs to all other international airports in the country; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) Delhi Airport is being developed as a major cargo hub and one of the features will be to have the proposed joint venture project in which the AAI will have minimum equity participation. Meantime works are in hand for expansion of the existing cargo terminal at Delhi at a cost of Rs. 42 crores and which are expected to be completed by April, 2000.

(b) and (c) Yes, Sir. Depending on the experience gained at Delhi Airport, such cargo hubs at other international airports in the country would be taken up.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते की दरें

*229. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है;

(ख) क्या पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के वेतनमानों तथा उनको मिलने वाले अन्य प्रकार के भत्तों में काफी वृद्धि की गई है; और क्या समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि करना वाजिब है; और

(ग) यदि हां, तो आपरेटिव स्टाफ सहित केन्द्रीय सरकार के समयोपरि भत्ते की संशोधित दरें लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ते की वर्तमान दरें चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतनमानों में संशोधन के पश्चात् मार्च 1991 में संशोधित (दिसम्बर 1990 से लागू) की गई थीं। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में समयोपरि भत्ते को खत्म करने की सिफारिश के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि स्टाफ कार ड्राइवर, कार्यरत कर्मचारियों (ऑपरेशनल स्टाफ) और प्रौद्योगिकी कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते का भुगतान उपरोक्त विषय पर जारी वर्तमान नियमों और अनुदेशों से अधिशासित करते हुए जारी रखा जाए। यह निर्णय लिया गया है कि समयोपरि भत्ते की पात्रता को और अधिक सीमित करने हेतु मामलों की समीक्षा के साथ-साथ सरकारी काम के हित के अनुरूप ही प्रतिबंधित करते हुए समयोपरि भत्ते के भुगतान की यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। तद्नुसार अगले आदेशों तक वर्तमान नियमों के अनुसार संबंधित कर्मचारी को पूर्व संशोधित वेतनमान/वेतन परिधि में वर्तमान आदेशों में निहित प्रयोग मूलक वेतन के आधार पर प्राप्त समयोपरि भत्ते का भुगतान जारी रखा गया है।

गुजरात में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ऋण

*230. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने गुजरात में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए